



Drishti IAS



करेंट अफेयर्स

हरियाणा

जुलाई

2024

(संग्रह)

Drishti, 641, First Floor, Dr. Mukharjee Nagar, Delhi-110009

Inquiry (English): 8010440440, Inquiry (Hindi): 8750187501

Email: [help@groupdrishti.in](mailto:help@groupdrishti.in)

# अनुक्रम

<b>हरियाणा</b>	<b>3</b>
➤ मुख्यमंत्री द्वारा कल्याणकारी योजनाओं के तहत लाभ जारी	3
➤ बकाया राशि को लेकर मरीजों के इलाज पर रोक	3
➤ यमूर्ति शील नागू: पंजाब एवं हरियाणा के मुख्य न्यायाधीश	4
➤ हरियाणा के शहर भारत के सबसे प्रदूषित शहरों में शामिल	5
➤ शंभू बॉर्डर पर बैरिकेड्स हटाने की प्रक्रिया	6
➤ IT सक्षम युवा योजना	7
➤ हरियाणा में नया OBC कोटा जोड़ा गया	7
➤ हरियाणा ने अग्निवीर कोटा बढ़ाया	8
➤ महामारी तैयारी नवाचारों का गठबंधन	9
➤ हरियाणा में लाल डोरा संपत्तियों पर बड़ा कदम	10
➤ शंभू बॉर्डर पर यथास्थिति	11
➤ हरियाणा में डॉक्टरों की हड़ताल	12
➤ हरियाणा में क्षीण मानसून	12
➤ मनु भाकर ने जीता ओलंपिक में कांस्य पदक	13

## हरियाणा

### मुख्यमंत्री द्वारा कल्याणकारी योजनाओं के तहत लाभ जारी

#### चर्चा में क्यों ?

हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पानीपत की अनाज मंडी में तीन कल्याणकारी योजनाओं के तहत 83,633 लाभार्थियों को ₹100.68 करोड़ के लाभ जारी किये।

#### मुख्य बिंदु:

- सामाजिक सुरक्षा पेंशन, डॉ. भीम राव अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना और मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत राज्य स्तरीय कार्यक्रम में लाभ वितरित किये गए।
- ◆ सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के 75,330 नए लाभार्थियों को पेंशन के रूप में ₹22.59 करोड़ की राशि जारी की गई।
- ◆ डॉ. बी.आर. अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत 2,003 लाभार्थियों को घर की मरम्मत के लिये ₹15.09 करोड़ की सहायता राशि जारी की गई।
- ◆ मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत 100 वर्ग गज भूमि के 6,300 लाभार्थियों को अधिकार पत्र और ₹1-1 लाख की वित्तीय सहायता के पत्र दिये गए।

#### डॉ. बी.आर. अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना

- इसकी शुरुआत हरियाणा राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2021 में की गई थी।
- इस योजना का मुख्य उद्देश्य उन सभी परिवारों को मकान की मरम्मत/नवीकरण के लिये अनुदान प्रदान करना है। जिनकी वार्षिक आय परिवार पहचान-पत्र में 1.80 लाख रुपए से कम या उसके बराबर है और मकान की मरम्मत की आवश्यकता है तो इस योजना के तहत उन्हें 80000 रुपए की राशि प्रदान की जाती है।

#### हरियाणा मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना

- वर्ष 2023 में शुरू की गई इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के कमजोर और निम्न आय वर्ग के परिवारों को सस्ती दरों पर आवास उपलब्ध कराना है।
- योजना के तहत उन लोगों को प्लॉट आवंटित किये जाएंगे जिनके पास आवास बनाने के लिये ज़मीन नहीं है।
- इससे राज्य के गरीब परिवारों का सामाजिक और आर्थिक विकास होगा तथा उन्हें सुरक्षित एवं स्थायी जीवन जीने का मौका मिलेगा।

### बकाया राशि को लेकर मरीजों के इलाज पर रोक

#### चर्चा में क्यों ?

हरियाणा के विभिन्न हिस्सों में निजी अस्पतालों ने राज्य सरकार द्वारा 200 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान न किये जाने के कारण केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत मुफ्त इलाज योजना और राज्य सरकार की चिरायु हरियाणा योजना के तहत मरीजों को भर्ती करना बंद कर दिया है।

#### मुख्य बिंदु:

- इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ( IMA ) के अनुसार, राज्य में लगभग 600 निजी अस्पताल आयुष्मान योजना के तहत सूचीबद्ध हैं और उन्होंने राज्य सरकार से बिलों का भुगतान जारी करने का अनुरोध किया था।

- ◆ हरियाणा में 74.33 लाख लाभार्थी चिरायु योजना के अंतर्गत तथा 28.89 लाख लाभार्थी आयुष्मान योजना के अंतर्गत आते हैं।
- ◆ इन योजनाओं के अंतर्गत प्रत्येक परिवार को द्वितीयक एवं तृतीयक देखभाल अस्पताल में भर्ती होने के लिये प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य कवरेज मिलता है।

### आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री- जन आरोग्य योजना ( AB PM-JAY )

- परिचय:
  - ◆ PM-JAY पूरी तरह से सरकार द्वारा वित्तपोषित विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है।
  - ◆ इसे 2018 में लॉन्च किया गया, यह द्वितीयक देखभाल और तृतीयक देखभाल के लिये प्रति परिवार 5 लाख रुपए की बीमा राशि प्रदान करती है।
  - ◆ स्वास्थ्य लाभ पैकेज में सर्जरी, चिकित्सा और डे केयर उपचार, दवाओं व निदान की लागत शामिल है।
- लाभार्थी:
  - ◆ यह एक पात्रता आधारित योजना है जो नवीनतम सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना ( SECC ) डेटा द्वारा पहचाने गए लाभार्थियों को लक्षित करती है।
  - ◆ राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) ने राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को शेष (अप्रमाणित) SECC परिवारों की पहचान करने के लिये समान सामाजिक-आर्थिक प्रोफाइल वाले गैर-सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना ( SECC ) लाभार्थी परिवार डेटाबेस का उपयोग करने हेतु लचीलापन प्रदान किया है।

### चिरायु हरियाणा योजना

- इसका उद्देश्य राज्य के ज़रूरतमंदों को मुफ्त इलाज की सुविधा उपलब्ध कराना है।
- इन परिवारों को 5 लाख रुपए तक का व्यय राज्य सरकार वहन करेगी।
- इस योजना का लाभ राज्य के 28 लाख से अधिक परिवारों को मिलेगा। योजना के विस्तार के साथ ही इसमें 12 लाख से अधिक नए गरीबी रेखा से नीचे (BPL) परिवारों को जोड़ा गया है।

### यमूर्ति शील नागू: पंजाब एवं हरियाणा के मुख्य न्यायाधीश

#### चर्चा में क्यों ?

हाल ही में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति शील नागू को पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है।

#### मुख्य बिंदु

उन्हें वर्ष 2011 में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। मामलों के निस्तारण के माध्यम से न्यायपालिका में उनका योगदान, 12 वर्षों से अधिक के अपने कार्यकाल के दौरान 499 से अधिक रिपोर्ट किये गए निर्णय हैं।

#### उच्च न्यायालय ( HC ) के न्यायाधीशों की नियुक्ति

- संविधान का अनुच्छेद 217: इसमें कहा गया है कि किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश ( CJI ), राज्य के राज्यपाल के परामर्श से की जाएगी।
- मुख्य न्यायाधीश के अलावा किसी अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श किया जाता है।
- परामर्श प्रक्रिया: उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सिफारिश एक कॉलेजियम द्वारा की जाती है जिसमें CJI और दो वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं।

- यह प्रस्ताव दो वरिष्ठतम सहयोगियों के परामर्श से संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा किया जाता है।
- सिफारिश मुख्यमंत्री को भेजी जाती है, जो केंद्रीय कानून मंत्री को प्रस्ताव राज्यपाल को भेजने की सलाह देता है।
- उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति इस नीति के आधार पर की जाती है कि राज्य का मुख्य न्यायाधीश संबंधित राज्य से बाहर का होगा।
- पदोन्नति पर निर्णय कॉलेजियम द्वारा लिया जाता है।

## हरियाणा के शहर भारत के सबसे प्रदूषित शहरों में शामिल

### चर्चा में क्यों ?

सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर ( CREA ) की एक रिपोर्ट के अनुसार, जून 2024 में भारत के शीर्ष 10 सबसे प्रदूषित शहरों में से आधे से अधिक शहर हरियाणा के होंगे।

### मुख्य बिंदु

- अध्ययन में शामिल 251 भारतीय शहरों में रोहतक सबसे प्रदूषित था। जून में रोहतक में **PM2.5 ( सूक्ष्म श्वास कण )** की औसत सांद्रता  $116\mu\text{g}/\text{m}^3$  थी, जो भारत में निर्धारित सुरक्षित स्तर  $60\mu\text{g}/\text{m}^3$  से दोगुनी से भी अधिक थी।
- जून में शीर्ष 10 सबसे प्रदूषित शहरों में रोहतक 28 बार शामिल रहा।
- उसके बाद चरखी दादरी एवं पंचकूला 16-16 बार, बल्लभगढ़ 11 बार और फरीदाबाद 10 बार शामिल रहा।
- कुल 60 शहर दैनिक सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में शामिल हुए। इनमें से 23 शहर कम-से-कम पाँच बार सूची में शामिल हुए। केवल फरीदाबाद ही राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम ( NCAP ) का हिस्सा है।
- शिकागो विश्वविद्यालय की 2021 वायु गुणवत्ता जीवन सूचकांक ( Air Quality Life Index- AQLI ) रिपोर्ट के अनुसार, भारत दुनिया का दूसरा सबसे प्रदूषित देश है, जहाँ सूक्ष्म कण वायु प्रदूषण (PM2.5) औसत नागरिक की जीवन प्रत्याशा को 5.3 वर्ष कम कर देता है।

### कणिका पदार्थ

- इसे कण प्रदूषण भी कहा जाता है, जो वायु में पाए जाने वाले ठोस कणों और तरल बूंदों के मिश्रण के लिये एक शब्द है। इससे श्वसन संबंधी समस्याएँ होती हैं तथा दृश्यता भी कम हो जाती है।
- इसमें शामिल है:
- **PM10**: साँस के साथ अंदर जाने वाले कण, जिनका व्यास आमतौर पर 10 माइक्रोमीटर और उससे छोटा होता है
- **PM2.5**: साँस के साथ अंदर जाने वाले सूक्ष्म कण, जिनका व्यास आमतौर पर 2.5 माइक्रोमीटर और उससे छोटा होता है।
- **PM के स्रोत**:
- इनमें से कुछ प्रत्यक्षतः जैसे- निर्माण स्थल, कच्ची सड़कें, खेत, अथवा आग किसी स्रोत से उत्सर्जित होते हैं।

### राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम

- इसे पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ( MoEFCC ) द्वारा जनवरी 2019 में लॉन्च किया गया था।
- समयबद्ध कटौती लक्ष्य के साथ वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिये एक राष्ट्रीय ढाँचा तैयार करने का यह देश में पहला प्रयास है।
- इसका उद्देश्य मोटे कणों ( 10 माइक्रोमीटर या उससे कम व्यास वाले कणिका पदार्थ (PM) या PM10) और बारीक कणों ( 2.5 माइक्रोमीटर या उससे कम व्यास वाले कणिका पदार्थ, या **PM2.5** ) की सांद्रता को अगले पाँच वर्षों में कम-से-कम 20% तक कम करना है, जिसकी तुलना के लिये आधार वर्ष 2017 रखा गया है।
- इसमें 132 गैर-प्राप्ति शहरों को शामिल किया गया है, जिनकी पहचान केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ( Central Pollution Control Board- CPCB ) द्वारा की गई थी।



## शंभू बॉर्डर पर बैरिकेड्स हटाने की प्रक्रिया

### चर्चा में क्यों ?

हाल ही में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने हरियाणा सरकार को अंबाला के पास शंभू बॉर्डर पर लगाए गए बैरिकेड्स हटाने का निर्देश दिया, जहाँ किसान अपनी मांगों के समर्थन में 13 फरवरी, 2024 से डेरा डाले हुए हैं।

### मुख्य बिंदु:

- हरियाणा सरकार ने फरवरी में अंबाला-नई दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर बैरिकेड्स लगा दिये थे।
- यह संयुक्त किसान मोर्चा ( गैर-राजनीतिक ) और किसान मज़दूर मोर्चा द्वारा फसलों के लिये न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की कानूनी गारंटी सहित विभिन्न मांगों का समर्थन करते हुए दिल्ली तक मार्च करने की योजना की घोषणा के बाद हुआ।
- सुरक्षा बलों द्वारा उनके मार्च को रोक दिये जाने के बाद फरवरी से ही किसान पंजाब और हरियाणा के बीच शंभू तथा खनौरी सीमा पर डटे हुए हैं।
- हालाँकि समय के साथ इस स्थल पर किसानों की संख्या में लगातार कमी आई है।

# ₹ न्यूनतम समर्थन मूल्य

## Minimum Support Price (MSP)

**वह दर जिस पर सरकार किसानों से फसल खरीदती है; किसानों द्वारा वहाँ किये गए उत्पादन लागत के कम-से-कम 1.5 गुणा की गणना के आधार पर**

**सिफारिश:**

- 'कृषि लागत और मूल्य आयोग' (CACP) द्वारा सरकार को 22 अधिदृष्ट फसलों के लिये 'न्यूनतम समर्थन मूल्य' (MSP) तथा गन्ने के लिये 'उचित और लाभकारी मूल्य' (FRP) की सिफारिश की जाती है।
- 22 अधिदृष्ट फसलें :
  - (14 खरीफ, 6 रबी और 2 अन्य वाणिज्यिक फसलें)
  - 7 अनाज- धान, गेहूँ, जौ, ज्वार, बाजरा, मक्का और रागी
  - 5 दालें- चना, अरहर/तूर, मूंग, उड़द और मसूर
  - 7 तिलहन- मूंगफली, सफेद सरसों/सरसों, सोयाबीन, सूरजमुखी, तिल, कुसुंभ और रामतिल
  - कच्चा कपास
  - कच्चा जूट
  - नारियल/गरी (कोपरा)

**MSP वह मूल्य है जिस पर सरकार को किसानों से अधिदृष्ट फसलों की खरीद करनी होती है, यदि बाजार मूल्य इससे कम हो जाता है**

**MSP की सिफारिश में प्रयुक्त कारक:**

- फसल की खेती में आने वाली लागत
- फसल के लिये आपूर्ति एवं मांग की स्थिति
- बाजार मूल्य प्रवृत्तियाँ
- अंतर-फसल मूल्य समता
- उपभोक्ताओं के लिये निहितार्थ (मुद्रास्फीति)
- पर्यावरण (मिट्टी तथा पानी के उपयोग)
- कृषि एवं गैर-कृषि क्षेत्रों के बीच व्यापार की शर्तें
- MSP की सिफारिश करते समय CACP द्वारा 'A2+FL' और 'C2' दोनों लागतों पर विचार किया जाता है।
- MSP का कोई वैधानिक समर्थन प्राप्त नहीं है - कोई भी किसान अधिकार के रूप में MSP की मांग नहीं कर सकता है

## IT सक्षम युवा योजना

### चर्चा में क्यों ?

हाल ही में हरियाणा सरकार ने युवा सशक्तीकरण और रोज़गार को बढ़ावा देने के लिये IT सक्षम युवा योजना वर्ष 2024 शुरू की है। इस योजना का लक्ष्य पहले चरण में 5,000 युवाओं को रोज़गार प्रदान करना है।

### मुख्य बिंदु:

- यह योजना व्यापक 'मिशन 60,000' का हिस्सा है। इसकी घोषणा वर्ष 2024-25 के बजट भाषण के दौरान की गई थी और इसका उद्देश्य गरीब परिवारों के कम-से-कम 60,000 युवाओं को रोज़गार प्रदान करना है।
- इस योजना के अंतर्गत, IT पृष्ठभूमि वाले स्नातक और स्नातकोत्तर आवेदक हरियाणा IT कार्यक्रम में भाग लेंगे, जो कि विशेष रूप से डिज़ाइन किया गया एक अल्पकालिक पाठ्यक्रम है, जो न्यूनतम तीन महीने का होगा।
- IT सक्षम युवा योजना में भाग लेने वालों को पहले छह महीनों के लिये 20,000 रुपए का मासिक पारिश्रमिक मिलेगा, जो नियोक्ता संस्थाओं द्वारा सातवें महीने से बढ़कर 25,000 रुपए हो जाएगा।
- यदि कोई 'IT सक्षम युवा' नियुक्ति हासिल करने में असमर्थ है, तो सरकार प्रति माह 10,000 रुपए का बेरोज़गारी भत्ता प्रदान करेगी
- इस योजना के लिये प्राथमिक प्रशिक्षण एजेंसियाँ हरियाणा राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड ( Haryana State Electronics Development Corporation Ltd.- HARTRON ), हरियाणा नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड ( HKCL ) और श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय ( Shri Vishwakarma Skill University- SVSU ) हैं।
- राज्य विश्वविद्यालय के रूप में SVSU, हरियाणा कौशल विकास मिशन ( Haryana Skill Development Mission- HSDM ) द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार अभ्यर्थियों को पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी करेगा।

### हरियाणा कौशल विकास मिशन ( Haryana Skill Development Mission- HSDM )

- इसकी स्थापना मई 2015 में राज्य सरकार द्वारा की गई थी।
- इसका उद्देश्य युवाओं को हरियाणा और भारत के आर्थिक एवं सर्वांगीण विकास में भाग लेने के लिये सशक्त बनाना है।
- यह विभागों में कौशल विकास योजनाओं को तैयार करने और संचालित करने के लिये सरकार के भीतर संपर्क का एकल बिंदु है।
- हरियाणा कौशल विकास मिशन ( HSDM ) एक एकीकृत मिशन के रूप में कार्य करता है जो राज्य के कौशल विकास लक्ष्य को प्राप्त करने में विभिन्न राज्य विभागों के प्रयासों को जोड़ता है।

## हरियाणा में नया OBC कोटा जोड़ा गया

### चर्चा में क्यों ?

हाल ही में हरियाणा सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग ( OBC ) के लिये क्रीमी लेयर की सीमा को ₹6 लाख की वार्षिक आय से बढ़ाकर ₹8 लाख कर दिया है। साथ ही पंचायती राज संस्थाओं और नगर पालिकाओं में OBC-B श्रेणी के लिये 5% कोटा भी पेश किया है।

### मुख्य बिंदु

- हरियाणा में OBC की जनसंख्या राज्य की जनसंख्या का लगभग 40% है और इसमें 78 जातियाँ शामिल हैं।
- OBC-B श्रेणी के लिये 5% आरक्षण OBC-A श्रेणी के लिये पहले से लागू 8% कोटे के अतिरिक्त होगा।

## अन्य पिछड़ा वर्ग ( OBC )

- OBC शब्द में नागरिकों के सभी वर्ग शामिल हैं जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं।
- सर्वोच्च न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि OBC की पहचान करने के लिये क्रीमी लेयर के बहिष्कार के सिद्धांत को लागू किया जाना चाहिये।
- क्रीमी लेयर को OBC श्रेणी के उन लोगों के वर्गों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो अब पिछड़े नहीं हैं और सामाजिक तथा आर्थिक रूप से देश के अन्य अग्रिम वर्गों के समान हैं।
- संवैधानिक प्रावधान
- संविधान के अनुच्छेद 15(4) के तहत राज्य को किसी भी सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग यानी OBC की उन्नति के लिये विशेष प्रावधान करने की शक्ति है।
- उन्नति के लिये विशेष प्रावधान" में कई पहलू शामिल हैं जैसे- शैक्षणिक संस्थानों में सीटों का आरक्षण, वित्तीय सहायता, छात्रवृत्ति, मुफ्त आवास आदि।
- अनुच्छेद 16(4) के तहत राज्य को OBC के पक्ष में नियुक्तियों या पदों के आरक्षण के लिये कानून बनाने का अधिकार है।

## हरियाणा ने अग्निवीर कोटा बढ़ाया

### चर्चा में क्यों ?

हाल ही में हरियाणा सरकार ने कांस्टेबल और वन रक्षक सहित अन्य पदों की भर्ती में अग्निवीरों के लिये 10% क्षैतिज आरक्षण की घोषणा की।

### मुख्य बिंदु:

- अग्निवीरों को सिविल पदों के लिये ग्रुप-सी की सीधी भर्ती में 5% और ग्रुप-बी की सीधी भर्ती में 1% क्षैतिज आरक्षण मिलेगा।
- जो निजी प्रतिष्ठान अग्निवीरों को 30,000 अथवा उससे अधिक मासिक वेतन देते हैं, उन्हें राज्य सरकार से 60,000 की वार्षिक सब्सिडी मिलेगी।
- व्यवसाय शुरू करने वाले अग्निवीर को 5 लाख तक के ऋण पर ब्याज लाभ मिलेगा।
- अग्निवीरों को शस्त्र लाइसेंस और सरकारी विभागों/बोर्डों/निगमों में रोजगार के लिये प्राथमिकता दी जाएगी।

## अग्निपथ योजना

### परिचय:

- यह देशभक्त और प्रेरित युवाओं को चार वर्ष की अवधि के लिये सशस्त्र बलों में सेवा करने का अवसर प्रदान करता है।
- इस योजना के तहत सेना में शामिल होने वाले युवाओं को अग्निवीर कहा जाएगा। युवा कम अवधि के लिये सेना में भर्ती हो सकेंगे।
- नई योजना के तहत प्रतिवर्ष लगभग 45,000 से 50,000 सैनिकों की भर्ती की जाएगी तथा इनमें से अधिकांश चार वर्षों में ही सेवा छोड़ देंगे।
- हालाँकि चार वर्षों के बाद बैच के केवल 25% लोगों को ही 15 वर्षों की अवधि के लिये उनकी संबंधित सेवाओं में वापस भर्ती किया जाएगा।

### PAY & BENEFITS: WHAT THE AGNIVEERS GET

- In Hand (70%)
- Contribution to Seva Nidhi (30%)\*

Similar contribution to corpus fund by Government of India\*\*



Total contribution to Seva Nidhi after 4 yrs  
**10.04 Lakh**  
(₹ 5.02 Lakh\* + ₹5.02 Lakh\*\*)

Exit After 4 Years } ₹11.71 Lakh as SevaNidhi Package  
(Including interest accumulated on the above amount as per the applicable rates)



### ● पात्रता मापदंड:

- ◆ यह केवल अधिकारी रैंक से नीचे के कार्मिकों के लिये है ( जो कमीशन प्राप्त अधिकारी के रूप में सेना में शामिल नहीं होते हैं ) ।
- ◆ कमीशन प्राप्त अधिकारी सेना के सर्वोच्च रैंक वाले अधिकारी होते हैं ।
- ◆ भारतीय सशस्त्र बलों में कमीशन प्राप्त अधिकारियों को एक विशेष रैंक प्राप्त है । वे प्रायः राष्ट्रपति की संप्रभु शक्ति के तहत कमीशन प्राप्त करते हैं और उन्हें आधिकारिक तौर पर देश की रक्षा करने का निर्देश दिया जाता है ।
- ◆ 17.5 वर्ष से 23 वर्ष की आयु के अभ्यर्थी आवेदन करने के पात्र होंगे ।

## महामारी तैयारी नवाचारों का गठबंधन

### चर्चा में क्यों ?

हाल ही में स्वास्थ्य अनुसंधान के लिये एशिया की पहली प्री-क्लीनिकल नेटवर्क सुविधा क्षेत्रीय जैव प्रौद्योगिकी केंद्र ( **Regional Centre of Biotechnology- RCB** ) में स्थापित की गई ।

- यह महामारी तैयारी नवाचार गठबंधन ( **Coalition of Epidemic Preparedness Innovations- CEPI** ) के हिस्से के रूप में फरीदाबाद में ट्रांसलेशनल स्वास्थ्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान ( **Translational Health Science & Technology Institute- THSTI** ) के अधीन है ।

### मुख्य बिंदु

- **CEPI** ने **BSL3 रोगजनकों** को नियंत्रित करने की क्षमता के आधार पर **BRIC-THSTI** को प्री-क्लीनिकल नेटवर्क प्रयोगशाला के रूप में चुना है ।
- ◆ यह 9वीं नेटवर्क प्रयोगशाला है और यह एशिया की पहली प्रयोगशाला होगी, जो अमेरिका, यूरोप तथा ऑस्ट्रेलिया की अन्य प्रयोगशालाओं में शामिल होगी ।
- ◆ यह पशु सुविधा देश की सबसे बड़ी सुविधाओं में से एक है, जिसमें लगभग 75,000 चूहों के साथ-साथ कमज़ोर प्रतिरक्षा वाले चूहे, खरगोश, हैमस्टर और गिनी पिग भी रखे गए हैं ।
- **जेनेटिकली डिफाइंड ह्यूमन एसोसिएटेड माइक्रोबियल कल्चर कलेक्शन ( Ge-HuMic ) फैसिलिटी** का भी उद्घाटन किया गया, जो अनुसंधान संस्थानों, विश्वविद्यालयों और उद्योगों को अनुसंधान तथा विकास के लिये माइक्रोबियल कल्चर को प्रदान करने के लिये एक “ भंडार ” के रूप में कार्य करेगा ।
- ◆ यह सुविधा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों तथा उद्योग के बीच सहयोग को सुविधाजनक बनाने के लिये एक नोडल संसाधन केंद्र के रूप में कार्य करेगी ।
- ◆ यह देश में शोधकर्ताओं के लिये क्रायो-संरक्षित भ्रूण और शुक्राणु सहित आनुवंशिक रूप से विशिष्ट रोगजनक-मुक्त जानवरों का भी भंडारण कर सकेगा ।

### नवाचार के लिये महामारी तैयारी गठबंधन ( CEPI )

- **CEPI** एक वैश्विक साझेदारी है जिसे भविष्य में महामारियों को रोकने के लिये टीके विकसित करने हेतु वर्ष 2017 में शुरू किया गया था ।
- **CEPI** की स्थापना **नॉर्वे** और **भारत** की सरकारों, **बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन**, **वेलकम ट्रस्ट** तथा **विश्व आर्थिक मंच ( World Economic Forum )** द्वारा **दावोस ( स्विट्ज़रलैंड )** में की गई थी ।
- **जैव प्रौद्योगिकी विभाग**, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा भारत सरकार **Ind-CEPI मिशन** ‘रैपिड वैक्सीन डेवलपमेंट के माध्यम से भारत केंद्रित महामारी की तैयारी: वैश्विक पहल के साथ गठबंधन कर भारत में वैक्सीन का विकास’ को लागू कर रही है
- इस मिशन के उद्देश्य **CEPI** के उद्देश्यों के अनुरूप हैं और इसका लक्ष्य भारत में महामारी की संभावना वाले रोगों के लिये टीकों तथा संबंधित क्षमताओं/प्रौद्योगिकियों के विकास को मजबूत करना है ।

## ट्रांसलेशनल स्वास्थ्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान ( THSTI )

- यह जैव प्रौद्योगिकी विभाग ( DBT ) का एक स्वायत्त संस्थान है।
- यह फरीदाबाद ( हरियाणा ) में स्थित है।

## जैव सुरक्षा स्तर ( BSL )

- BSL ( Biosafety Levels ) का उपयोग प्रयोगशाला में श्रमिकों, पर्यावरण और जनता की सुरक्षा के लिये आवश्यक सुरक्षात्मक उपायों की पहचान करने के लिये किया जाता है।
- जैविक प्रयोगशालाओं में संचालित गतिविधियों और परियोजनाओं को जैव सुरक्षा स्तर के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है।
- चार जैव सुरक्षा स्तर BSL-1, BSL-2, BSL-3 और BSL-4 हैं, जिसमें BSL-4 नियंत्रण का उच्चतम ( अधिकतम ) स्तर है।

## हरियाणा में लाल डोरा संपत्तियों पर बड़ा कदम

### चर्चा में क्यों ?

हाल ही में हरियाणा सरकार ने शहरी क्षेत्रों में लाल डोरा संपत्तियों से संबंधित लंबे समय से चल रहे मुद्दों को हल करने के लिये एक व्यापक रजिस्ट्री पहल शुरू की है।

- मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति मालिकों और दीर्घकालिक किरायेदारों दोनों को लाभ मिलेगा।

### मुख्य बिंदु

- लाल डोरा का सीमांकन वर्ष 1908 में ब्रिटिश शासन के दौरान किया गया था, जिसमें औपचारिक बस्तियों के बाहर कृषि के लिये क्षेत्रों को चिह्नित किया गया था।
- ◆ इन भूमियों को भवन निर्माण उपनियमों और नगरपालिका विनियमों से छूट दी गई है, लेकिन मालिकों को अक्सर स्वामित्व सिद्ध करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिससे संपत्ति के लेन-देन एवं वित्तीय सेवाओं तक पहुँच में बाधा उत्पन्न होती है।
- ◆ राज्य सरकार ने गाँवों को लाल डोरा प्रतिबंधों से मुक्त करने हेतु उपाय लागू किये, जिससे वहाँ रहने वालों को संपत्ति के अधिकार प्राप्त करने की अनुमति मिल सके।
- स्वामित्व योजना का उद्देश्य लाल डोरा क्षेत्रों में संपत्ति के स्वामित्व अधिकारों को सुव्यवस्थित करना और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना है।
- मुख्यमंत्री गुरुग्राम में एक राज्य स्तरीय समारोह में लाभार्थियों को संपत्ति प्रमाण-पत्र और रजिस्ट्री वितरित करेंगे, जो हरियाणा में शहरी विकास के लिये एक महत्वपूर्ण क्षण होगा।

## मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना

- इसे राज्य में 20 वर्षों से अधिक समय से किराए या पट्टे पर चल रही नगर पालिकाओं की वाणिज्यिक भूमि का स्वामित्व देने के लिये डिज़ाइन किया गया है।
- इस योजना के तहत, जो व्यक्ति किराए या पट्टे के माध्यम से 20 वर्षों से भूमि पर कब्जा कर रहे हैं, उन्हें कलेक्टर दर के 80% तक भुगतान पर स्वामित्व अधिकार दिया जा रहा है।
- इसी तरह ज़मीन पर कब्जे के वर्षों की सीमा के अनुसार अलग-अलग दरों पर कलेक्टर रेट देना होगा, जैसे 25 वर्ष के लिये कलेक्टर रेट का 75%, 30 वर्ष के लिये 70%, 35 वर्ष के लिये 65%, 40 वर्षों के लिये 60%, 45 वर्षों के लिये 55% तथा 50 वर्षों के लिये 50% भुगतान पर स्वामित्व अधिकार देने का प्रावधान है।

## स्वामित्व योजना

- स्वामित्व का तात्पर्य गाँवों का सर्वेक्षण और ग्रामीण क्षेत्रों में उन्नत प्रौद्योगिकी के साथ मानचित्रण से है।

- यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसे 24 अप्रैल, 2021 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय स्तर पर लॉन्च किया गया था।
- इसका उद्देश्य ग्रामीण भारत के लिये एकीकृत संपत्ति सत्यापन समाधान प्रदान करना है।
- ग्रामीण आवासीय क्षेत्रों का सीमांकन ड्रोन सर्वेक्षण और CORS ( Continuously Operating Reference Stations अर्थात् निरंतर प्रचालन संदर्भ स्टेशन ) नेटवर्क का उपयोग करके किया जाएगा, जो 5 सेमी. की मानचित्रण सटीकता प्रदान करता है।
- इससे गाँवों के बसे हुए ग्रामीण क्षेत्रों में मकान रखने वाले ग्रामीण परिवार स्वामियों को 'अधिकारों का अभिलेख ( Record of Rights )' उपलब्ध हो सकेगा।
- यह वर्ष 2021-2025 के दौरान पूरे देश के लगभग 6.62 लाख गाँवों को कवर करेगा।

## शंभू बॉर्डर पर यथास्थिति

### चर्चा में क्यों ?

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने शंभू बॉर्डर पर प्रदर्शनकारियों से संपर्क कर उनकी मांगों का समाधान खोजने के लिये प्रतिष्ठित व्यक्तियों की एक स्वतंत्र समिति बनाने का प्रस्ताव रखा था।

### मुख्य बिंदु:

- शीर्ष न्यायालय हरियाणा सरकार की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के उस निर्देश को चुनौती दी गई है जिसमें अंबाला के पास शंभू बॉर्डर पर एक सप्ताह के भीतर बैरिकेड्स हटाने का निर्देश दिया गया है, जहाँ किसान 13 फरवरी, 2024 से डेरा डाले हुए हैं।
- ◆ फरवरी में हरियाणा सरकार ने संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा की दिल्ली तक मार्च की योजना के जवाब में अंबाला-नई दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर बैरिकेड्स लगा दिये थे।
- वे फसलों के लिये न्यूनतम समर्थन मूल्य ( Minimum Support Price- MSP ) की कानूनी गारंटी सहित अन्य मांगों की वकालत कर रहे थे।

## ₹ न्यूनतम समर्थन मूल्य Minimum Support Price (MSP)

वह दर जिस पर सरकार किसानों से फसल खरीदती है; किसानों द्वारा वहाँ किये गए उत्पादन लागत के कम-से-कम 1.5 गुणा की गणना के आधार पर

- सिफारिश:
- 'कृषि लागत और मूल्य आयोग' (CACP) द्वारा सरकार को 22 अधिदृष्ट फसलों के लिये 'न्यूनतम समर्थन मूल्य' (MSP) तथा गन्ने के लिये 'उचित और लाभकारी मूल्य' (FRP) की सिफारिश की जाती है।
- 22 अधिदृष्ट फसलें :
  - (14 खरीफ, 6 रबी और 2 अन्य वार्षिक फसलें)
- 7 अनाज- धान, गेहूँ, जौ, ज्वार, बाजरा, मक्का और रागी
- 5 लालें- चना, अरहर/गुर, मूंग, उड़द और मसूर
- 7 तिलहन- मूंगफली, सफेद सरसों/सरसों, सोयाबीन, सूरजमुखी, तिल, कुसुंध और रामतिल
- कच्चा कपास
- कच्चा जूट
- नारियल/गरी ( कोपरा )

MSP वह मूल्य है जिस पर सरकार को किसानों से अधिदृष्ट फसलों की खरीद करनी होती है, यदि बाजार मूल्य इससे कम हो जाता है

- MSP की सिफारिश में प्रयुक्त कारक:
  - ◆ फसल की खेती में आने वाली लागत
  - ◆ फसल के लिये आपूर्ति एवं मांग की स्थिति
  - ◆ बाजार मूल्य प्रवृत्तियाँ
  - ◆ अंतर-फसल मूल्य समता
  - ◆ उपभोक्ताओं के लिये निहितार्थ (मुद्रास्फूर्ति)
  - ◆ पर्यावरण (मिट्टी तथा पानी के उपयोग)
  - ◆ कृषि एवं गैर-कृषि क्षेत्रों के बीच व्यापार की शर्तें
  - ◆ MSP की सिफारिश करते समय CACP द्वारा 'A2+FL' और 'C2' दोनों लागतों पर विचार किया जाता है।
  - ◆ MSP का कोई वैधानिक समर्थन प्राप्त नहीं है - कोई भी किसान अधिकार के रूप में MSP की मांग नहीं कर सकता है



- सुरक्षा बलों द्वारा उनके मार्च को रोक दिये जाने के बाद फरवरी से ही किसान पंजाब और हरियाणा के बीच शंभू तथा खनौरी सीमा पर डटे हुए हैं।

## हरियाणा में डॉक्टरों की हड़ताल

### चर्चा में क्यों ?

हाल ही में हरियाणा में सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों ने अपनी विभिन्न मांगों पूरी न होने के विरोध में अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की, जिससे सरकारी अस्पतालों में सेवाएँ बाधित हो गई हैं।

### प्रमुख बिंदु

- हड़ताल की शुरुआत हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विसेज़ एसोसिएशन ने की थी, जो राज्य में सरकारी डॉक्टरों का प्रतिनिधित्व करने वाला संगठन है
- डॉक्टर अपने लिये एक विशेष विभाग की स्थापना करने और कैरियर उन्नति कार्यक्रम की मांग कर रहे हैं जो केंद्र सरकार के लिये कार्य करने वाले उनके समकक्षों के साथ उन्हें समानता प्रदान करेगा
- ◆ डॉक्टरों की अन्य मांगों में वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों की सीधी भर्ती पर रोक लगाना और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिये बॉण्ड की राशि कम करना शामिल है
- राज्य सरकार ने निकाय से रोगियों पर इस हड़ताल के प्रभाव पर विचार करने की अपील की है।

## हरियाणा में क्षीण मानसून

### चर्चा में क्यों ?

भारतीय मौसम विभाग के अनुसार, क्षीण मानसून के कारण हरियाणा को मानसून वर्षा पर निर्भर किसानों के लिये राहत प्रयासों और जल की कमी का समाधान करने के उपायों पर विचार करने की आवश्यकता पड़ सकती है।

### मुख्य बिंदु

- आँकड़ों के अनुसार, राज्य में 114.6 मिमी. वर्षा के साथ औसत वर्षा में 38% की कमी दर्ज की गई।
- ला नीना परिघटना में देरी के कारण जून और जुलाई माह के दौरान इस क्षेत्र में मानसून की स्थिति “क्षीण चरण” में थी। ला नीना एक ऐसी परिघटना है जिसके फलस्वरूप भारतीय उपमहाद्वीप में अनुकूल मानसून वर्षा होती है।
- ◆ अगस्त माह के अंत में या सितंबर की शुरुआत में ला नीना परिघटना के संपन्न होने के साथ प्रभावित क्षेत्रों की वर्षण स्थिति में सुधार होने की उम्मीद है।
- सेंटर फॉर स्टडी ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड पॉलिसी ( CSTEP ) थिंक-टैंक के एक शोधकर्ता के अनुसार हिंद महासागर द्विध्रुव ( Indian Ocean Dipole- IOD ) के रूप में जानी जाने वाली एक अन्य जलवायवीय परिघटना की स्थिति वर्तमान में उदासीन है। यह परिघटना हिंद महासागर के जल स्तर को प्रभावित करती है।
- ◆ एक घनात्मक हिंद महासागर द्विध्रुव ( IOD ) के फलस्वरूप मानसून के दौरान अनुकूल वर्षा होती है।
- मानसून के निवर्तन ( वापसी ) के बाद उम्मीद से कम वर्षा की स्थिति में विशेषज्ञों ने संकेत दिया कि सरकार को आकस्मिक योजनाओं को लागू करने की आवश्यकता होगी।
- ◆ इन योजनाओं में किसानों को अतिरिक्त सहायता प्रदान करना, सिंचाई प्रयोजनों के लिये जल की उपलब्धता सुनिश्चित करना तथा अन्य जल संरक्षण उपायों को क्रियान्वित करना शामिल हो सकता है।

## ला नीना

- स्पेनिश भाषा में ला नीना का अर्थ होता है छोटी लड़की। इसे कभी-कभी अल विंजो, एंटी-अल नीनो या “एक शीत घटना” भी कहा जाता है।
- ला नीना घटनाएँ पूर्व-मध्य विषुवतीय प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में औसत समुद्री सतही तापमान से निम्न तापमान की द्योतक हैं।
- इसे समुद्र की सतह के तापमान में कम-से-कम पाँच क्रमिक त्रैमासिक अवधि में 0.9°F से अधिक की कमी द्वारा दर्शाया जाता है।
- जब पूर्वी प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में जल का तापमान सामान्य की तुलना में कम हो जाता है तो ला नीना की परिघटना देखी जाती है, जिसके परिणामस्वरूप पूर्वी विषुवतीय प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में एक उच्च दाब की स्थिति उत्पन्न होती है।

## हिंद महासागर द्विध्रुव (IOD)

- IOD, जिसे भारतीय नीनो भी कहा जाता है, एल नीनो के समान ही एक घटना है जो पूर्व में इंडोनेशियाई और मलेशियाई तटरेखा तथा पश्चिम में सोमालिया के पास अफ्रीकी तटरेखा के बीच हिंद महासागर के अपेक्षाकृत छोटे क्षेत्र में घटित होती है।
- अल नीनो दक्षिणी दोलन (El Nino Southern Oscillation- ENSO) घटना की तुलना में अल नीनो एक सामान्य से अधिक गर्म चरण है, जिसके दौरान भारत सहित विश्व के कई क्षेत्रों में आमतौर पर तापमान गर्म और वर्षा सामान्य से कम होती है।
- ऐसे में भूमध्य रेखा के साथ समुद्र का एक किनारा दूसरे की तुलना में गर्म हो जाता है।
- जब हिंद महासागर का पश्चिमी भाग, विशेषकर सोमालिया तट के करीब पूर्वी हिंद महासागर की तुलना में गर्म हो जाता है, तब इसे घनात्मक IOD कहा जाता है।
- जब पश्चिमी हिंद महासागर ठंडा होता है तब इसे ऋणात्मक IOD कहते हैं।

## मनु भाकर ने जीता ओलंपिक में कांस्य पदक

### चर्चा में क्यों ?

हाल ही में हरियाणा के झज्जर की रहने वाली मनु भाकर ने पेरिस 2024 ओलंपिक में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में कांस्य पदक और साथ ही 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ट टीम इवेंट में भी कांस्य पदक जीता।

- वह ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला निशानेबाज हैं।

मुख्य बिंदु

- 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में पेरिस 2024 ओलंपिक में भारत का पहला पदक है और लंदन 2012 गेम्स के बाद भारत के लिये शूटिंग में पहला ओलंपिक पदक है।
- उन्होंने सरबजोत सिंह के साथ 10 मीटर मिक्स्ट टीम पिस्टल इवेंट में भी कांस्य पदक जीता।
- वह राज्यवर्द्धन सिंह राठौर (2004 एथेंस), अभिनव बिंद्रा (2008 बीजिंग), विजय कुमार (2012 लंदन) और गगन नारंग (2012 लंदन) के बाद ओलंपिक पदक जीतने वाली पाँचवी भारतीय निशानेबाज हैं।
- मनु ने एशियाई खेलों (2022), विश्व चैंपियनशिप, बाकू (2023), एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप, चांगवोन (2023), विश्व कप, भोपाल (2023), विश्व चैंपियनशिप, काहिरा (2022), विश्व विश्वविद्यालय खेल, चेंगदू (2021) खेल आयोजनों में भी पदक जीते हैं।
- मनु ने एशियन गेम्स (2022), वर्ल्ड चैंपियनशिप, बाकू (2023), एशियन शूटिंग चैंपियनशिप, चांगवोन (2023), विश्व कप, भोपाल (2023), वर्ल्ड चैंपियनशिप, काहिरा (2022), वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स, चेंगदू (2021) खेल स्पर्धाओं में भी पदक जीते हैं।



## ओलंपिक

### परिचय:

- ◆ ओलंपिक एक अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजन है जो प्रत्येक चार वर्ष में आयोजित किया जाता है।
- ◆ ओलंपिक का लक्ष्य खेल के माध्यम से मनुष्य का विकास करना और विश्व शांति में योगदान देना है।
- ◆ ओलंपिक में शामिल खेल: समर गेम्स, विंटर गेम्स और यूथ ओलंपिक गेम्स।
- ◆ इतिहास और उत्पत्ति
- ◆ ओलंपिक की शुरुआत लगभग 3,000 वर्ष पूर्व प्राचीन ग्रीस के पेलोपोनिस क्षेत्र में हुई थी।
- ◆ हालाँकि सटीक आरंभ तिथि की अनिश्चितता अभी भी बनी हुई है, सामान्यतः ऐतिहासिक अभिलेखों में इसका वर्ष 776 ईसा पूर्व उल्लेखित है।
- ◆ पियरे डी. कूबर्टिन की योजना के आधार पर पहला आधुनिक ओलंपिक वर्ष 1896 में एथेंस, ग्रीस में आयोजित किया गया था।

### ओलंपिक रिंग्स:

- ◆ ओलंपिक प्रतीक में एक सफेद पृष्ठभूमि पर विभिन्न रंगों ( नीला, पीला, काला, हरा और लाल ) के पाँच इंटरलॉकिंग रिंग्स होते हैं।
- ◆ ये रिंग्स विश्व के पाँच महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करते हैं और खेलों के माध्यम से देशों की एकता एवं विविधता का प्रतीक हैं।

